चिंतन शिविर, उदयपुर : बहुत लम्बे समय बाद कांग्रेस की होर्डिंग्स में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का चित्र नज़र आया।

'चिंतन शिविर के पश्चात् और भी प्रभावी स्वरूप में उभरेगी कांग्रेस'

खुद की भूमिका पर बोले पायलट, जो जिम्मेदारी पार्टी देगी वह निभाऊंगा।

जयपुर, 14 मई (का.प्र.)। कांग्रेस में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि जब शिविर में भाग लेने वाले नेताओं में 50 प्रतिशत नेता 40 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो स्पष्ट है कि पार्टी युवाओं को महत्व दे रही है। उनकी खुद की आगामी भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल पर पूर्व उपमख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, वह निभाऊंगा। पहले भी मैं पार्टी की ओर से दी गई जिम्मेदारियों को निभाता आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर कोई चुनौती दे सकता है तो वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। देश में वर्तमान समय में जो ज्वलंत मुद्दे है, केन्द्र सरकार धर्म, जात-पात की बात करके उनसे जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को केन्द्र में काबिज हुए 8 साल हो गये है। उसे इन आठ वर्षों के कार्यों का लेखा-जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इन 8 सालों में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। महंगाई चरम पर है। पैट्रोल-डीजल, रसोई गैस सहित रोजमर्रा की वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। देश का युवा वर्ग हताश है। बेरोजगारी बढ़ गई है, नई नौकरियां नहीं निकाली जा रही है। लोगों के काम-धन्धे ठप्प हो गये है। सरकार के स्वयं के आंकड़े बताते है कि देश में भुखमरी, कुपोषण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।

उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करके आगामी रणनीति तैयार करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में उदयपुर में 13 मई से 15 मई, 2022 तक तीन दिवसीय "नव संकल्प चिंतन शिविर" का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशभर से 400 से अधिक कांग्रेसजन भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिविर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहले से अधिक रखा गया है। साथ ही 50 प्रतिशत से अधिक प्रतिभागी 40 वर्ष के कम उम्र के हैं। उन्होंने बताया कि इस चिंतन शिविर में विभिन्न विषयों की अलग-अलग समितियां बनायी गई है। आर्थिक मामलों से संबंधी समिति में उन्हें भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले है तथा दो वर्ष बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यह चिंतन शिविर बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर बुलाया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आयेंगे और कांग्रेस पार्टी नई ऊर्जा व मजबूती के साथ नौजवानों व मध्यम वर्ग की आवाज बनकर उभरेगी।

राहुल व प्रियंका...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस असमंजस की स्थिति को समाप्त करना ही होगा। जहाँ वरिष्ठ नेताओं के बीच ज़ुबानी झड़पें होती रहीं, वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अशोक गहलोत तथा उनकी सरकार पर कटाक्ष किये। बघेल ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी द्वारा बताई गई योजनाएं क्रियान्वित कर दी हैं लेकिन उनके सफल एवं लोकप्रिय न होने का कारण यह रहा कि अन्य मुख्यमंत्रियों, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री, ने उन्हें लागू नहीं किया। उनका संकेत न्याय स्कीम की ओर था। उन्होंने कहा कि अगर ये योजनाएं लागू कर दी गई होतीं, तो इससे अर्थव्यवस्था को मदद मिली होती तथा भाजपा पर ऐसी और योजनाएं शुरु करने का दबाव पड़ता।

जो चीज राहुल गांधी के लिये बहुत बड़ा धक्का सिद्ध हो सकती है, वह है- युवा कांग्रेस और एन.एस.यू.आई. के चुनाव, जिसका बड़ा प्रयोग राहुल ने उस समय किया था, जब वे कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तथा वह विवादास्पद भी रहा था। ऐसी संभावना है कि इस बिन्दु को दरकिनार कर दिया जाये क्योंकि इसके खिलाफ कई नेता बोले थे तथा उन्होंने कहा था कि इसे शुन्य एवं अकृत (नल एंड वॉइड) कर दिया जाना चाहिये।

उन तौर-तरीकों को लेकर गहरी अप्रसन्नता व्यक्त की गई, जिस तरीके से युवा कांग्रेस और एन.एस.यू.आई. चलाये जा रहे हैं, तथा किसी भी स्तर पर उनकी कोई प्रभावी भूमिका दिखाई नहीं दे रही है। उस तरीके पर भी प्रतिक्रिया दिखाई दी, जिस तरीके से ए.आई.सी.सी. सचिव नियुक्त किये जा रहे हैं, क्योंकि ये अपरिचित लोग हैं तथा इन्हें संगठन का कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी को भी नहीं मालूम कि इन लोगों की नियुक्ति क्यों और कैसी की जा रही हैं। ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि जी-23 की इस मांग को सी.डब्ल्यु.सी. स्वीकार कर सकती है कि चुनाव समिति के बजाय, संसदीय बोर्ड की नियुक्ति होनी चाहिये। इसके साथ भी इस बात का निर्णय होने की भी संभावना है कि इसके लिये चुनाव कराये जायेंगे या यह बोर्ड मनोनीत होगा। पार्टी ने कहा है कि संगठन के पदों में से 50 प्रतिशत पद 50 वर्ष से कम उम्र के नेताओं के लिये होंगे तथा संगठन में कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य के लिये आरक्षण होना चाहिये। यह भी संभावित है कि महिला आरक्षण बिल, जो पहले अस्वीकार हो चुका है, में कोटा के अंदर कोटा की पूर्ववर्ती माँग स्वीकार कर ली जाये।

बदलाव नजर आया होर्डिंग्स में

उदयपुर, 14 मई (का.प्र.)। यहां चल रहे कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में पार्टी में काफी कुछ बदलने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और बयान भी आ रहे हैं, किन्तु पार्टी में सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद क्या बदलाव आने हैं यह तो 1 दिन बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस शिविर से पहले कांग्रेस में जो बदलाव देखने को मिला है उसमें प्रमुख बदलाव यह है कि कांग्रेस ने शहर भर में जो होर्डिंग्स लगाए हैं उनमें उन नेताओं को स्थान मिला है, जिन्हें कांग्रेस आमतौर पर याद नहीं करती है। इस बार लगाए गए पोस्टर्स कुछ खास हैं। आमतौर पर कांग्रेस के शिविरों, अधिवेशनों या सम्मेलनों के पोस्टरों में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के साथ गांधी परिवार को तवज्जो दी जाती है या फिर संबंधित प्रदेश के मुख्यमंत्री को। शहर के प्रमुख रास्तों पर लगे होर्डिंग्स में महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, मनमोहन सिंह के साथ स्वतंत्रता सेनानियों को भी बराबर महत्व दिया गया है। इन होर्डिंग्स में पीवी नरसिम्हा राव, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, रवींद्र नाथ टैगोर, सुभाष चन्द्र बोस और सरोजनी नायडू भी शामिल हैं। आमतौर पर कांग्रेस कार्यक्रमों के पोस्टरों में गांधी परिवार या मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष के ही चेहरे नजर आते हैं। कांग्रेस ने इन पोस्टर के जरिए परिवारवाद के आरोपों का मौन जवाब देने की कोशिश की है। उदयपुर एयरपोर्ट से से लेकर शहर में कई जगह ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं।

■ **नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, भगत सिंह, गोखले और सुभाष चन्द्र बोस को भी जगह दी कांग्रेस ने।**

रेणु जी का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्यमंत्री राज्य के क्षेत्रीय अखबरों से अपना अनुसरण करवाना चाहता है और उनसे यह उम्मीद करते हैं कि उसकी राजनीति, उसकी नीतियों, वे उसके सुशासन की कमी और उसके द्वारा की जा रही प्रतिशोध की राजनीति पर सवाल खड़े किए बिना उनके नेतृत्व के प्रशस्ति गान लिखे।

इस मॉडल का अनुसरण संभवत: भाजपा द्वारा किया जाता है, लेकिन यह निश्चित रूप से कांग्रेस की कार्यशैली का हिस्सा कभी नहीं रहा, जिसने ऐसी सैन्सरशिप कभी लागू नहीं की।

इसके साथ ही अशोक गहलोत ने ताज अरावली पार्किंग स्थल पर लगाए मीडिया टैंट के आस पास भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की है। यह गहलोत सरकार द्वारा लगाया गया ए.आई.सी.सी. मीडिया सैन्टर है।

यह नोटिस किया गया कि सी.आई.डी. और पुलिस, दोनों के कर्मी सादे कपड़ों में बड़ी संख्या में पत्रकारों के बीच बैठे थे। क्या यह जासूसी, निगरानी या पत्रकारों की बात सुनने के लिए है या यह देखने के लिए कि क्या रिपोर्ट्स दी जा रही है तथा क्या इन रिपोर्ट्स में मुख्यमंत्री और उनकी कार्यशैली की आलोचना है। लगता है कि अशोक गहलोत स्वयं को अधिकाधिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि वह अपना मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए जरूरत से अधिक सक्रिय हैं। उदयपुर की तपती गर्मी, जिसमें दिन का तापमान बहुत अधिक है, मीडिया के अरैन्जमैन्ट्स एक तपते टैन्ट में किए गए है, जहां ए.सी. नहीं चल रहे है वैसे बात तो बहुत गंभीर व बड़ी है, लेकिन संक्षिप्त में इतना ही कहा जा सकता है कि वास्तव में जिस जगह शिविर चल रहा है, वहां मीडिया को एक्सैस नहीं दिया गया है।

स्थानीय नागरिकों एवं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गई है। अब शिविर स्थल से पांच किलोमीटर दूर से तीन चैक पोस्ट बनाकर गहन जांच के बाद ही केवल पासधारियों को ही उस मार्ग पर जाने की अनुमति दी जा रही है। चिकित्सा दल: इधर, शिविर में प्रतिभागिता कर रहे दो नेताओं की तबीयत बिगड़ने पर एक को चिकित्सालय भेजा गया तथा दूसरे को शिविर स्थल पर ही उपचार दिया गया। इसके बाद तत्काल चिकित्सा दल बुलवाया गया।

संयुक्त चिकित्सा निदेशक जेड ए काजी और जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश खराड़ी मय स्टाफ शिविर स्थल पहुंचे। अब एक चिकित्सा दल शिविर समाप्त होने तक शिविर स्थल पर ही रहेगा।

सुनील जाखड़ के इस्तीफे ने बिगाड़ा कांग्रेस के चिंतन शिविर का मिजाज

जाखड़ बोले, राहुल चापलूसों से बचें और पार्टी की कमान संभालें

उदयपुर, 14 मई (का.प्र.)। कांग्रेस जहां तीन दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कर पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन की ओर कदम बढ़ा रही वहीं पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सुनील जाखड़ ने ना सिर्फ पार्टी छोड़ी, बल्कि पार्टी नेतृत्व सहित नेतृत्व के चापलूसों पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की , लेकिन साथ में यह भी कहा कि वे चापलूसों से पीछा छुड़ा ले क्योंकि इसकी वजह से कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। उनके निशाने पर खास तौर से अंबिका सोनी, हरीश रावत और हरीश चौधरी के अलावा चरणजीत सिंह चन्नी भी रहे। दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि पार्टी को सुनील जाखड़ को नहीं खोना चाहिए था। वह सोने की कीमत के जैसे हैं। कुछ बातें टेबल पर की जा सकती थीं। जैसे ही सुनील जाखड़ के पार्टी छोड़ने की खबर आई, इसका असर उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर पर भी नजर आया। ठीक उसी समय संवाददाता सम्मेलन में मौजूद कांग्रेस के नेता इस संबंध में सवालों से बचते नजर आए। हालांकि इस बारे में पंजाब के प्रभारी रहे हरीश रावत से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने से पहले उन्हें सोनिया गांधी से बात करनी चाहिए थी। वहीं खुद पर लगाए गए आरोपों को लेकर रावत ने कहा कि वे उन्हें छोटे भाई के तौर पर ही देखते हैं। इस मामले में जब उदयपुर में मौजूद पंजाब में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा से बात करनी चाही, तो उन्होंने इस बारे में जवाब देने से स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। जाखड़ ने सोनिया गांधी के लिए कहा कि वह पूरे देश में राजनीति करें, लेकिन पंजाब को बख्श दें। जाखड़ ने कहा कि आतंकवाद के दौर में और वर्ष 1984 में जब ए के-47 भी पंजाब में धर्म और जात-पात का भेदभाव न कर सकी, उसे कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने चुनाव के वक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे उदयपुर में कांग्रेस की हालत देख तरस आ रहा है। कितने नेता सिर्फ चीयरलीडर्स हैं, और कितने कड़वी और सच्ची बात कहेंगे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चिंतन शिविर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा कुछ नहीं। अगर वाकई चिंता होती तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हार के लिए कमेटी बनाती। इसका कारण खोजती कि कैसे 403 में से 300 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार को 2 हजार वोट भी नहीं मिले। इससे ज्यादा वोट तो पंचायत के उम्मीदवार को ही मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसका जिम्मेदार उम्मीदवार नहीं बल्कि शीर्ष नेता और पार्टी नेतृत्व है, जिसने कांग्रेस की यह दुर्दशा की है। जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस को उम्मीद थी कि उत्तराखंड और पंजाब में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। यहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या कोई बताएगा कि उत्तराखंड के सीएम प्रत्याशी हरीश रावत का एक पैर पंजाब में और दूसरा देहरादून में क्यों था, क्या सोचकर रावत को प्रभारी बनाकर भेजा गया ? क्या रावत की मंशा थी कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। हरीश रावत को किए की सजा मिली। उन्होंने कहा कि पंजाब ने बहुत बुरे दिन देखे हैं। पंजाब को धर्म के आधार पर नहीं देख सकते। पंजाब एक है। अंबिका सोनी की जुबान ने कांग्रेस का बेड़ा डुबोया। सिख, सिखी और कांग्रेस के माथे पर सोनी ने कलंक लगाया। सोनी ने हिंदुओं को बदनाम किया। कहा गया कि हिंदू सीएम बन गया तो पंजाब में आग लग जाएगी। यह काम तो आतंकवाद में ए के -47 भी नहीं कर पाई।

■ **हरीश रावत बोले, सोनिया गांधी से बात करनी चाहिए थी, प्रताप बाजवा जवाब देने से बचते रहे।**

दिल्ली आग की घटना में 29 लोग अभी भी लापता

नई दिल्ली, 14 मई (वार्ता)। राष्ट्रीय राजधानी में पश्चिमी दिल्ली के मुंडका मैट्रो स्टेशन के पास एक चार मंजिला इमारत में लगी आग को 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी दो दर्जन से अधिक लोग लापता हैं और उनके परिजन अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं।

जानकारी के अनुसार, इस चार मंजिला इमारत में लगी आग में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए, जबकि 29 अन्य लापता हो गए। इसके साथ ही मामले की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दिए हैं। संजय गांधी अस्पताल के शवगृह के बाहर करीब एक दर्जन परिवार अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश में जुटे हैं।

सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी तो हुई है, मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस नेतृत्व उनके साथ इंसाफ करेगा

उदयपुर, 14 मई (का.प्र.)। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में आए प्रियंका गांधी के नजदीकी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर सचिन पायलट के साथ अन्याय होने का बयान देते हुए कहा है कि सोनिया गांधी ने नेताओं को इशारा कर दिया है। उन्होंने नेताओं से त्याग करने की बात कहकर साफ मैसेज दे दिया है। इसका असर आगे देखने को मिलेगा। इसमें राजस्थान या किसी प्रदेश के नेता विशेष की बात नहीं है, सबके समझने की बात है। कांग्रेस में मंथन-चिंतन के बाद परिवर्तन का नियम है।

उन्होंने कहा कि 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए तब प्रदेशाध्यक्षों को मुख्यमंत्री बनाया गया था। पंजाब में अमरिंदर सिंह प्रदेशाध्यक्ष थे तो उन्हें सीएम बनाया गया। एमपी में कमलनाथ प्रदेशाध्यक्ष थे उन्हें सीएम बनाया, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल प्रदेशाध्यक्ष थे, उन्हें सीएम बनाया, लेकिन राजस्थान में उस समय कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। सचिन पायलट के साथ थोड़ी नाइंसाफी तो हुई है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस नेतृत्व उनके साथ इंसाफ करेगा। आचार्य प्रमोद ने कहा- सोनिया गांधी ने कल अपने भाषण में बहुत कुछ साफ कर दिया है। भारत की में राजनीति में सोनिया ने जीवन का आधा हिस्सा देश और कांग्रेस के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने तीन बार पीएम पद कुर्बान कर दिया। उन्होंने कल बड़ा इशारा किया है। चिंतन शिविर का मोटिव सोनिया गांधी ने समझा दिया है। इसका मकसद है कि चिंतन-मंथन के बाद परिवर्तन होना है। राजस्थान में सोनिया गांधी के मैसेज के मायनों के सवाल पर आचार्य प्रमोद ने कहा कि उन्हें राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बारे में कमेंट करने का अधिकार नहीं है, लेकिन, आप इंतजार कीजिए। कृष्णम इससे पहले भी कई बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी कर चुके हैं और सीएम अशोक गहलोत को लेकर भी तंज कस चुके हैं। उनके ताजा बयान को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

'सैलून में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिखा है, कि इस सैलून में कार्यरत टैक्नीशियन, विजय और मोहित के पास "हेयर ट्रांसप्लान्ट" करने के लिए किसी "मैडिकल कोर्स" या डिग्री का प्रमाण पत्र नहीं है। इसलिए विजय को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, वहीं मोहित के खिलाफ "वॉरन्ट" जारी कर दिया गया है।

अदालत ने अपने आदेश में यह भी टिप्पणी की है कि देश भर में ऐसे सैलून पनप रहे हैं, जहां स्व प्रचारित "टैक्नीशियन", "हेयर ट्रांसप्लान्ट और कॉस्मैटिक सर्जरी" करते हैं, "जो नैतिकता और निर्धारित प्रक्रिया के नियमों के विरूद्ध है।" अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा कि "हेयर ट्रांसप्लान्ट" जैसी सर्जरी एक प्रशिक्षित सर्जन और "डर्मिटोलॉजिस्ट" की देखरेख में ही की जानी चाहिए। अदालत ने आगे कहा कि जिन सैलून में ऐसी सर्जरी की जाती है, वहां लोगों को ऐसी सर्जरी से संबंधित जोखिमों के बारे में भी सूचित नहीं किया जाता, जिसको जानकार ही लोग ऐसी सर्जरी करवाने के लिए अपनी रज़ामंदी दे सकते हैं। जिन लोगों से उनकी रज़ामंदी ली गई होती है उन्हें यह जानकारी ही नहीं होती की यह सर्जरी केवल प्रशिक्षित डॉक्टर ही कर सकते हैं।

आदेश में आगे कहा गया है कि करोना महामारी के समय इन सैलूनों में वृद्ध तथा वे व्यक्ति जो "कोमॉर्बिडिटीज़" से ग्रस्त हैं उन्हें ऐसे सैलूनों से ज्यादा खतरा है। अदालत के अनुसार एक प्रशिक्षित डॉक्टर के अभाव में सैलून में कराई जा रही सर्जरी से किसी निर्दोष व्यक्ति का स्थाई नुकसान हो सकता है या उक्त मामले की तरह जान भी गंवानी पड़ सकती है। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को अपनी रिपोर्ट के साथ सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने के आदेश दिये हैं।

आगामी राज्यसभा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से कम 37 वोट चाहिये। वर्तमान स्थिति में, भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के सात सदस्य आसानी से जीत जायेंगे। सपा तथा मित्र दल- राष्ट्रीय लोक दल एवं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी- अपने 125 विधायकों के दम पर, 3 सीटें जीत जायेंगे। 11वीं सीट के लिये भाजपा और सपा के बीच "टाई" की स्थिति रहेगी तथा इस सीट का जीत अन्य दलों के समर्थन पर निर्भर होगी, जिनमें राजा भैया की जनसत्ता कांग्रेस तथा मायावती की बसपा भी शामिल हैं, जिनके पास क्रमश: 2 तथा 1 विधायक हैं।

कांग्रेस के कपिल सिब्बल, बसपा महासचिव सतीश चन्द्र मिश्रा तथा समाजवादी पार्टी रेवती रमणसिंह उन सदस्यों में शामिल हैं, जिनका उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त हो रहा है।

मिश्रा तथा अशोक सिद्धार्थ के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद, इस सदन में रामजी गौतम बसपा के अकेले सदस्य बचेंगे।

सेवानिवृत्त होने वाले पाँच भाजपा सदस्य हैं- ज़फर इस्लाम, शिव प्रताप शुक्ला, संजय सेठ, सुरेन्द्र नागर तथा जय प्रकाश निषाद।

महाराष्ट्र से छ: राज्यसभा सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिनमें शामिल हैं- केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल, पूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा कांग्रेस सदस्य पी. चिदम्बरम तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी सदस्य प्रफुल्ल पटेल, शिव सेना के संजय राउत एवं भाजपा के विनय सहस्रबुद्धे और विकास हरिभाऊ महात्मे।

राजस्थान से सेवानिवृत्त होने वाले चारों सदस्य भाजपा के हैं। ये हैं- भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर, पूर्व केन्द्रीय मंत्री अलफॉन्स कन्ननथानम, राम कुमार वर्मा तथा पूर्व डूँगरपुर नरेश हर्षवर्धन सिंह। चूंकि कांग्रेस सत्ता में है, यह इस बार कम से कम तीन सीट तो जीत ही जायेगी।

पंजाब से सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य हैं- वरिष्ठ कांग्रेस नेता अंबिका सोनी तथा अकाली दल नेता बलविन्दर सिंह। सत्तारूढ़ आप दोनों ही सीटों को आसानी से समेट लेगी।

ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरु

लखनऊ, 14 मई। ज्ञानवापी मस्जिद में शनिवार को पहले दिन के सर्वे का काम शनिवार को पूरा हो गया है। दोपहर 12 बजे तक यह सर्वे का काम हुआ। पहले दिन 4 घंटे तक सर्वे का काम चला। इस दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया है कि सर्वे के दौरान हमारी उम्मीदों के मुताबिक साक्ष्य मिले। हालांकि अभी इनके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। वकील कह रहे हैं कि यह मामला गोपनीय है। जो कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। वादी पक्ष के वकील ने कहा तहखानों के सर्वे का काम आधा हो गया, आधा कल होगा।

कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे का काम पूरा होने के बाद कहा कि सर्वे का काम शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एक दो दिन और चलेगा सर्वे का काम। कितने तहखाने मिले इस पर वकीलों ने कहा अभी इस बारे में नहीं बता सकते। 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान दोनों तहखानों वीडियोग्राफी की गई। कल 8 बजे से फिर सर्वे का काम शुरू होगा। कल पूरा हो गया सर्वे का काम तो ठीक, नहीं तो अगले दिन सर्वे का काम संपन्न कराया जाएगा। ज्ञानवापी में नंदी के आसपास सर्वे किया गया। जानकारी के मुताबिक सर्वे टीम के साथ वादी-प्रतिवादी पक्ष भी परिसर में मौजूद थे। वहीं एहतियातन मस्जिद परिसर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। मस्जिद परिसर के 500 मीटर के दायरे में दुकानों को बंद कर दिया गया। एक कि.मी. के दायर में 1500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को तैनात रहे।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक मस्जिद के चप्पे-चप्पे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। मस्जिद के तहखाने का भी सर्वे कराया गया। इस सर्वे को पूरा कराने की जिम्मेदारी डी.एम. और पुलिस कमिश्नर को दी गई थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि वादी, प्रतिवादी, वकील, एडवोकेट कमिश्नर और उनके सहायक भी सर्वे में मौजूद रहेंगे। कोर्ट के आदेश मुताबिक आज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे का काम संपन्न हुआ। कोर्ट ने आदेश दिया था कि एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ही रहेंगे। वहीं कोर्ट ने विशाल सिंह और अजय सिंह को सहायक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट ने पूरी सर्वे रिपोर्ट 17 मई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ धाम के करीब स्थित है और स्थानीय अदालत महिलाओं के एक समूह द्वारा इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने दैनिक प्रार्थना की अनुमति मांगने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही है।

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय
(एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भारत सरकार)
संसद के अधिनियम द्वारा 2008 में स्थापित

प्रवेश प्रारम्भ : 2022-2023

आईएमयू-सीईटी को 11 जून 2022 तक स्थगित किया गया है। आईएमयू-सीईटी हेतु पंजीकरण की अन्तिम तिथि 24 मई 2022 तक बढ़ा दी गई है।

डीजीएस अनुमोदित समुद्री कार्यक्रम हेतु आवेदन करना चाहते हैं? कृपया आईएमयू-सीईटी हेतु पंजीकरण करें

भारत के किसी भी संस्थान में डीजीएस द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों (बी.टेक. (एमई)/बी.एससी. (एनएस)/डीएनएस) में कार्यग्रहण हेतु आईएमयू-सीईटी को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

यूजी कार्यक्रम

बी.टेक-मरीन इंजीनियरिंग (चेन्नई, कोलकाता और मुम्बई पोर्ट कैम्पस)	बी.एससी.-समुद्री विज्ञान (चेन्नई, कोच्चि, नवीं मुम्बई)	बीबीए-लॉजिस्टिक्स, रिटेलिंग एंड ई-कॉमर्स- (चेन्नई/कोच्चि)
बी.टेक.-नेवल आर्किटेक्चर एंड ऑशियन इंजीनियरिंग (विशाखापत्तनम)	बी.एससी.-जहाज निर्माण व मरम्मत (जहाज तकनीकी महाविद्यालय) (केवल एक सम्बद्ध संस्थान में प्रस्तावित)	* बीबीए - अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड मैरिटाइम लॉजिस्टिक्स (विशाखापत्तनम)
समुद्री विज्ञान में डिप्लोमा (डीएनएस) (चेन्नई और नवीं मुम्बई)		

पीजी कार्यक्रम

एमबीए - पोर्ट एंड शिपिंग मैनेजमेंट (चेन्नई/कोच्चि)	एम.टेक.-ड्रेजिंग एंड हार्बर इंजीनियरिंग (विशाखापत्तनम)	एम.टेक.- मरीन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट (कोलकाता)
एमबीए-इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट - (चेन्नई/कोच्चि/ कोलकाता/ विशाखापत्तनम)	एम.टेक.-नेवल आर्किटेक्चर एंड ऑशियन इंजीनियरिंग (विशाखापत्तनम)	मरीन इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (मुम्बई पोर्ट कैम्पस में आयोजित किया जाएगा)

बीबीए, पीजीडीएमई और बीएसई - एसबीआर को छोड़कर कार्यक्रमों में प्रवेश आईएमयू-सीईटी के आधार पर है। लेटरल एंट्री (द्वितीय वर्ष) प्रवेश पोर्टल खुला है। पूरे भारत में किसी भी डीजीएस अनुमोदित एमटीआईएस में लैटरल एंट्री के प्रवेश हेतु आईएमयू सीईटी अनिवार्य है।

पंजीकरण और जानकारी हेतु www.imu.edu.in लॉग ऑन करें।

आईएमयू-सीईटी और प्रस्तावित कार्यक्रमों पर जानकारी हेतु कृपया क्यूआर कोड स्कैन करें अथवा वेबिनर ज्वाइन करने के लिये 15.05.2022 (रविवार) को अप. 4.00 बजे यूट्यूब लिंक - https://youtu.be/Vi9pUH19FpQ देखें।

सीईटी हैल्पलाइन- 044-24539027 044-24539028

पूछताछ हेतु, हमें ई-मेल करें cet22@imu.ac.in bba22@imu.ac.in

* बीबीए - अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड मैरिटाइम लॉजिस्टिक्स के विद्यार्थी उनकी अप्रेंटिसशिप अवधि के दौरान रु. 7500/- प्रति माह का एक स्टाईपेंड प्राप्त करेंगे।

Follow us @IMUHeadquarters @IMU_Headquarters @IMU_HQ

DAVP No.37208/12/0003/2223

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600